मुक्त व्यापार की नीति और ब्रिटिश साम्राज्य का हित

– 1813 के बाद ब्रिटिश उद्योग का उत्पाद भारत में आने लगा पहले तो पाबन्दी हटी और बाद में टैरिफ को भी घटाते हुए 1890 तक लगभग शून्य पर ला दिया गया। इस दौर में ब्रिटिश ही नहीं अन्य देश के उद्योगपति भी अपना माल भारत में ला सकते थे क्योंकि सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाया था। सरकार का दावा था कि यह नीति इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके कारण सर्वांगिण विकास होगा। भारत के उद्योग को इस नीति के कारण नुकसान हुआ क्योंकि ये अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाये। जर्मनी, जापान और अमेरिका चुकि स्वतंत्र राष्ट्र थे इसलिए वहाँ की सरकारों ने अपने देश के उद्योग की जरूरत के अनुसार नीति अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से उनका बचाव किया। भारतीय राष्ट्रीय नेता भी भारत की सरकार पर उन्हीं देशों की सरकारों की तरह नीतियाँ अपनाने का दबाव डाल रहे थे। लेकिन भारत की सरकार भारत के उद्योग के नुकसान के बावजूद मुक्त व्यापार की नीति चलाती रही क्योंकि यह नीति इंग्लैण्ड के उद्योग के लिए लाभदायक थी। चुकि इंग्लैण्ड विश्व का औद्योगिक नेता था इसलिए उन्हें यह पता था कि मुक्त व्यापार की नीति के रास्ते उन्हें दो फायदा होगा।–

(i) भारत के ~~उद्योग~~ बाजार पर अंग्रेजी उद्योग का प्रभुत्व

Scanned with CamScanner

साम्राज्यवादी चरित्र भी पर्दे के अन्दर ढका रहेगा।

1932 में ओटावा सम्मेलन के तहत भारत ने भी साम्राज्यिक वरीयता की नीति अपनाया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य देशों ने आपस में एक दूसरे को वरीयता देते हुए कर का कम दर रखने का फैसला किया और बाहर के देशों पर ज्यादा दर में कर लगाया जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत पहले वरीयता आधारित व्यापार की शुरुआत हुई और उसके बाद मुक्त व्यापार की नीति का आगमन हुआ। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विकास की दिशा उल्टी रही क्योंकि सरकार पूँजीवाद का नाम लेकर साम्राज्यवादी नीतियाँ अपना रही थी और चुकि 1813 से 1920 तक उन्हें भारत के बाजार में किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ रहा था इसलिए तब तक मुक्त व्यापार की नीति जारी रही। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारत के बाजार में अमरीकी और जापानी वस्तुओं के प्रवेश में तेजी आई और अंग्रेजी प्रभुत्व को चुनौती मिलने लगी इसी चुनौती से बचने के लिए साम्राज्यिक वरीयता की नीति अपनायी गयी। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने इस नीति का भी प्रबल विरोध किया था क्योंकि वो इसके पीछे के साम्राज्यवादी डिजाइन को समझ रहे थे।

Scanned with CamScanner